THE MINISTER OF STATE (INDEPENDENT CHARGE) OF THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRI H. R. BHARDWAJ): (a) and (b) Yes, Sir. Annual Plan for Maharashtra (1991-92) was approved at Rs. 2500 crores, with criteria based normal Central assistance (gross) of Rs. 380.31 crore (including Central assistance for special problems of the State). Furthermore it was agreed that the outlay could be enhanced to Rs. 3000 crores, subject to additional resources of Rs. 500 crores (including Rs. 75 crores for Bombay city, comprising of Rs. 50 crores as Central assistance and Rs. 25 crores as additional Central transfers) to be raised by the State and Central Governments together.

MR. CHAIRMAN: Question Hour is over.

—

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Industrial growth in West Bengal

*242. PROF. SOURENDRA BHATTACHARJEE: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether the Central Government have been discussing with the Government of West Bengal the matter relating to industrial growth in the State and that of pending projects which are still awaiting clearance of the Central Government;

(b) whether any headway has been made so far;

(c) whether delay is causing enormous losses both in terms of production and employment potentialities in the State; and

(d) if so, the outcome thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI P. J. KURIEN): (a) Yes, Sir.

(b) to (d) Conceptualisation and implementation of projects is an ongoing exercise requiring coordination between various agencies of the State and Central Government. A number of projects in West Bengal have been cleared and we are in constant dialogue with them for effective and expeditious implementation.

राज्य स्तरीय पुरस्कार प्राप्त फिल्मों का दूरदर्शन के राष्ट्रीय नेटवर्क पर प्रसारण

*243. **श्री विश्वासराव रामराव पाटिल:** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्य-स्तरीय पुरस्कार प्राप्त फिल्मों को दूरदर्शन के राष्ट्रीय नेटवर्क पर प्रसारित करने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार राज्य-स्तरीय पुरस्कार प्राप्त किन्हीं मराठी फिल्मों का प्रसारण दूरदर्शन पर करने का विचार रखती है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास): (क) और (ख) रविवार अपराह्न राष्ट्रीय नेटवर्क पर दिखाए जाने के लिए दूरदर्शन द्वारा उन फीचर फिल्मों पर पहले से ही विचार किया जा रहा है, जिन्होंने निम्नलिखित वर्गों में से कोई भी राज्य-स्तरीय पुरस्कार प्राप्त किया हो:

1. सर्वोत्तम फीचर फिल्म के लिए राज्य पुरस्कार

2. सर्वोत्तम निर्देशन के लिए राज्य पुरस्कार

3. किन्हीं दो राज्य पुरस्कारों से पुरस्कृत फिल्में।

(ग) जी, हां।

(घ) दूरदर्शन ने प्रसारण के लिए पहले ही राज्य स्तर पर पुरस्कृत ग्यारह मराठी फिल्मों का चयन किया है। ये फिल्में, दूरदर्शन की कार्यक्रम आवश्यकताओं के अनुसार, विभिन्न भाषाओं की अन्य पात्र फिल्मों के साथ दिखाई जाएंगी।

पॉम आयल बीजों का उत्पादन

@246क. **सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा :**

डा० जितेन्द्र कुमार जैन :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बायोटेक्नोलॉजी विभाग ने पॉम आयल बीजों के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक तथा महाराष्ट्र की सरकारों के सहयोग से एक योजना लागू की है;

(ख) यदि हां, तो यह योजना कब शुरू की गई और इसके अब तक क्या परिणाम प्राप्त हुये हैं ;

(ग) क्या सरकार ने इस योजना के कार्यान्वयन में आ रही कठिनाइयों का पता लगाया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या उपचारी उपाय किये गये हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा) : (क) और (ख) जी हां। यह तेल ताड़ प्रदर्शन नामक परियोजना भारत सरकार द्वारा 1988-89 में आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र की सरकारों के साथ उपर्युक्त प्रत्येक राज्य में लगभग एक हजार हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र में तेल ताड़ कृषि की व्यवहार्यता प्रदर्शित करने के लिये शुरू की गई थी। ये परियोजनाएं 5 वर्ष में पूरी की जानी है। प्रत्येक तेल ताड़ प्रदर्शन परियोजना भारत सरकार एवं सम्बद्ध राज्य सरकार के बीच 50 : 50 के आधार पर बजटगत लागत साझीदारी पटर्न पर कार्यान्वित की जा रही है। तेल ताड़ प्रदर्शन परियोजना क्षेत्र हैं : आंध्र प्रदेश कृष्णा, पश्चिम गोदावरी एवं पूर्व गोदावरी जिले, कर्नाटक—शिमोगा जिला और महाराष्ट्र—सिन्धुदुर्ग जिला (कोंकण क्षेत्र)।

सभी तीन तेल ताड़ प्रदर्शन परियोजनाओं के लिये भारत सरकार एवं सम्बद्ध राज्य सरकार स्वीकृति आदेश 1988-89 में जारी किये गये थे। सभी तेल ताड़ प्रदर्शन परियोजनाओं में दोनों अर्थात् मैसर्स ए. एस. डी. लिमिटेड, कोस्टारिका से प्राप्त आयातित उत्तम बीजों तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से प्राप्त स्वदेश में ही उत्पादित बीजों से पौध तैयार की गई है। तीन राज्यों में पौध रोपण क्षेत्र निर्धारित किया गया है। आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटक में 100 प्रतिशत क्षेत्र में पौध रोपण किया गया है। महाराष्ट्र में 75% क्षेत्र इसके अंतर्गत है और शेष क्षेत्र में इस मौसम में पौध रोपण किया जा रहा है। संसाधन संयंत्रों की स्थापना के लिये भी प्रयास शुरू किये गये हैं जो फल-गुच्छों की प्रथम कटाई तक तैयार हो जायेंगे।

(ग) और (घ) इस योजना के कार्यान्वयन में अभी तक कोई प्रमुख कठिनाइयां नहीं आई हैं। परियोजनाओं की प्रगति बहुत संतोषजनक रही है।

Repository of Computer Software for Sanskrit Studies and Training

*248. SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR: Will the PRIME MINISTER be please to state:

(a) whether there is any repository of Computer Software Packages for Sanskrit studies and training.

@यथा तारांकित प्रश्न 267, 13 सितम्बर, 1991 से स्थानांतरित ।